भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में माह जून, 2020 का मासिक सारांश।

<u>गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) के तहत सामुदायिक शौचालय</u>

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडीशा और झारखंड के 116 चयनित जिलों के लिए 20 जून, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान आरंभ किया गया ताकि 125 दिनों की अवधि के लिए अवसंरचना निर्माण के माध्यम से प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर चलाई जाने वाली चिह्नित 25 गतिविधियों में से एक है। अभियान के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण के संबंध में दिनांक 20.06.2020 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया था। इस पहल की जानकारी देने के लिए सभी छः जीकेआरए राज्यों के साथ एक विडियो कांफेरेंस भी आयोजित की गई थी। मास मीडिया और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से विडियो तथा रेडियो प्रचार का उपयोग करके आईईसी संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यों के साथ इस विषय पर बनाई जाने योग्य दीवार की चित्रकारी के स्टेंसिल भी साझा किए गए हैं।

<u>खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस बेसलाइन, घोषणा और सत्यापन</u>

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II के लिए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस बेसलाइन अध्ययन करवाने के संबंध में दिनांक 19.06.2020 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया था। दिनांक 26.06.2020 को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) प्लस बेसलाइन सर्वेक्षण 2020 पर एक वेब आधारित सेमीनार (वेबीनार) भी आयोजित की गई थी। इस वेबीनार में 200 से अधिक राज्यों/ जिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें विकास भागीदारों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.3030 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II के तहत ओडीएफ प्लस की परिभाषा और ओडीएफ घोषणा और सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत ऐडवाइज़री भी जारी की गई थी।

<u>आईईसी अभियान और पहलें</u>

i) **बदल कर अपना व्यवहार करेंगे कोरोना पर वार।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 'कोरोना वायरस से लड़ने के लिए' एक समर्पित आईईसी अभियान की योजना बनाई गई और उसका कार्यान्वयन किया गया। अभियान के भाग के रूप में व्यक्तिगत साफ-सफाई और सामाजिक दूरी पर बल देते हुए ग्रामीण समुदाय को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने हेतु उपयुक्त प्रचार सामग्री तैयार की गई। मास मीडिया और साथ ही सोशल मीडिया पर व्यापक उपयोग करने हेतु लघु फिल्म और ऑडियो स्पॉट बनाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु दीवार पर चित्रकारी के स्टेंसिल बनाए गए। नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इन प्रचार सामग्रियों को अधिक प्रचार-प्रसार हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डीओएसईएल, डीओवाईए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डीओपीआर तथा डीओआरडी को भेजा गया।

ii) स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत

विशेष रूप से वर्तमान समय में शौचालयों के नियमित उपयोग द्वारा ओडीएफ को स्थायी बनाए रखने के महत्व पर बल देते हुए एक आईईसी अभियान तैयार किया गया और इसे आरंभ किया गया। अभियान में साबुन से हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की व्यक्तिगत साफ-सफाई की आदत पर भी बल दिया गया। उक्त संदेशों पर विभिन्न प्रचार सामग्री तैयार की गई और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनका व्यापक उपयोग किया गया। सभी राज्यों को ये प्रचार सामग्री भेजी गई और उसके बाद इनके कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य के साथ विडियो कांफेरेंस की गई।

iii) सामुदायिक शौचालय अभियान

15 जून, 2020 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एक गहन आईईसी अभियान नामतः सामुदायिक शौचालय अभियान (एसएसए) 2020 प्रारंभ किया गया जो 15 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव करने के लिए जिलों को अपने पंचायतों और गांवों को प्रेरित करने के प्रति लक्षित किया गया है। इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य बढ़ती-घटती तथा प्रवासी आबादी को गांव के सार्वजनिक और अधिक भीड-भाड़ वाले स्थानों पर सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराकर गुणवत्ता पूर्ण स्वच्छता उपलब्ध कराना है ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य बेहतर रहे।

<u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निगरानी</u>

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) बजट के तहत निधियों के उपयोग और विश्व बैंके के तहत निष्पादन प्रोत्साहन अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करने हेतु दिनांक 04.06.2020 को नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडीशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्वच्छता के एसीएस/ प्रधान सचिव/ सचिव और प्रभारी मिशन निदेशकों के साथ विडियो कांफेरेंस आयोजित की गई।

<u>मलीय कचरा प्रबंधन (एफएसएम)</u>

दिनांक 25.06.2020 को नई दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा प्रबंधन (एफएसएम) पर एक वेब आधारित सेमीनार (वेबीनार) आयोजित किया गया। इस वेबीनार में 500 से अधिक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया और इसमें विकास भागीदारों ने अपने अनुभव साझा किए।

<u>जल जीवन मिशन के लिए वार्षिक कार्य योजना (2020-21)</u>

वर्ष 2024 तक 100% घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की वार्षिक कार्य योजना (2020-21) और ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों की समीक्षा करने हेतु 01-26 जून, 2020 तक मेघालय, मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंश्चिम बंगाल और राजस्थान के साथ विडियो कांफेरेंस (वीसी) आयोजित किए गए।